>

Title: Need to expedite the procurement of paddy by FCI from farmers in Bihar at remunerative price.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): बिहार में कृषि में अभूतपूर्व क्रांति हुई है जो बिहार अन्न के मामले में केंद्र पर आश्रित था आज वह लाखों टन धान और गेहूँ केंद्रीय पूल में देने के लिए प्रयासरत है। केंद्र पंजाब, हरियाणा को ही सरप्लस राज्य के रूप में खाद्यान्न के मामले में जानता था। अब उत्तर प्रदेश, बिहार भी पंजाब और हरियाणा से उत्पादन के मामले में बढ़त हासिल करने के लिए आतुर है। लाखों टन धान होने के बावजूद भारतीय खाद्य निगम किसानों से धान खरीदने से आनाकानी कर रहा है। किसानों को डिस्ट्रेस सेल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिलने के कारण उनकी खेती मुसीबत बनती जा रही है। जहाँ धान का मूल्य 1250/- रूपये निर्धारित किया गया है पर उस मूल्य पर किसानों से धान नहीं खरीदी जा रही है। किसान हमारी कृषि व्यवस्था की रीढ़ है। केंद्रीय सरकार के भारतीय खाद्य निगम के इस दृष्टिकोण से किसानों में आक्रोश है। आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने के लिए बाध्य हो रहे हैं।

अतः केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि वह निर्धारित मूल्यों पर बिहार के किसानों से पैक्स के द्वारा धान खरीदने की एक वृहद योजना बनाएं। इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।